Regarding Minimum Support Price.-laid

श्री राजा राम सिंह **(**काराकाट**) :** ऐतिहासिक किसान आंदोलन और भारत सरकार तथा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बीच हुए समझौते को तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है । हालांकि, 09/12/2021 को SKM को भेजे गए पत्र में जिन मांगों पर केंद्र सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, वे अब तक पूरी नहीं हुई हैं । किसानों के आंदोलन के दबाव में ही सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े थे । इस संघर्ष में 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई, फिर भी सरकार ने अब तक उनके परिवारों को मुआवज़ा देने का कोई प्रयास नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने के लिए प्रस्तावित समिति के गठन की स्थिति क्या है? इस समिति के गठन और उसमें SKM को शामिल करने में अब तक देरी क्यों हो रही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इस समिति का गठन कब करने जा रही है? इसी तरह, कृपया राज्यवार जानकारी दें कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और किन राज्यों में अब भी ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें किसान आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ केस वापसी नहीं हुई है ।